नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 122
दि. 04.02.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

लोकसभा में भाषण से शुरु हुआ टकराव, निलंबन तक पहुंचा विवाद

अमरिंदर सिंह राजा वारिंग
लुधियाना, पंजाब
कांग्रेस

प्रशांत पडोले
भंडारा गोंदिया, महाराष्ट्र
कांग्रेस

मणिकम टैगोर
विरुधुनगर, तमिलनाडु
कांग्रेस

किरण कुमार रेड्डी
भोंगीर, तेलंगाना
कांग्रेस

हिबी ईडन
एर्नाकुलम, केरल
कांग्रेस

गुरजीत औजला
अमृतसर, पंजाब
कांग्रेस

डीन कुरियाकोस
इडुक्की, केरल
कांग्रेस

एस वेंकटेशन
मदुरै सांसद
CPI(M)

जीएनएस)। नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर लगातार दूसरे दिन भी संसद की कार्यवाही भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। मंगलवार को सदन में जो कुछ हुआ, उसने संसदीय परंपराओं, मर्यादा और विपक्ष–सत्ता पक्ष के बीच बढ़ते टकराव को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। राहुल गांधी जब दोपहर करीब दो बजे बोलने के लिए खड़े हुए, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामला कुछ ही घंटों में आठ सांसदों के निलंबन और संसद भवन के बाहर प्रदर्शन तक पहुंच जाएगा।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की एक अप्रकाशित किताब में छपे लेख का हवाला देने की कोशिश की। उनका कहना था कि 2020 के भारत–चीन संघर्ष से जुड़े तथ्यों को सदन के सामने रखना जरूरी है और उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज दिखाने की कोशिश की, सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार आपत्ति जतानी शुरू कर दी। शोर-शराबा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही चलाना

मुश्किल हो गया। राहुल गांधी बार-बार कहते रहे कि उन्हें अपनी बात रखने दी जाए, लेकिन हंगामे के कारण वे करीब 14 मिनट तक बोलने का प्रयास ही करते रह गए।

इससे पहले सोमवार को भी राहुल गांधी लगभग 46 मिनट तक अपनी बात रखने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन तब भी भारी हंगामे के कारण उनका भाषण पूरा नहीं हो सका था। लगातार दूसरे दिन यही स्थिति बनने से विपक्ष में नाराजगी और बढ़ गई। पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए राहुल गांधी को रोकते हुए अन्य दलों के सांसदों को बोलने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि, राहुल के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल, तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय और डीएमके के डी.एम. कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब नेता प्रतिपक्ष को ही बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही, तो वे भी चर्चा में भाग नहीं लेंगे।

इसके बाद विपक्षी सांसदों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। वे नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। शोर-शराबे के बीच कुछ सांसदों ने पीठासीन अधिकारी के आसन की ओर कागज उछाल दिए। यह दृश्य लोकसभा के इतिहास में बेहद असामान्य माना जा रहा है। स्पीकर ने बार-बार अपील की कि व्यवस्था बनाए रखी जाए, लेकिन स्थिति संभल नहीं सकी। आखिरकार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

दोपहर तीन बजे जब चौथी बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो पीठासीन अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि स्पीकर के आसन की ओर कागज फेंकना गंभीर अनुशासनहीनता है और ऐसे सांसदों के नाम दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा कि इस कृत्य में शामिल सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के डीन कुरियाकोस, किरण रेड्डी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िग, मणिकम टैगौर, गुरजीत औजला, हिबी इडेन, वेंकेट रमन और प्रशांत पडोले शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने सदन की गरिमा भंग की और पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना की।

निलंबन की कार्रवाई के बाद भी राजनीतिक माहौल शांत नहीं हुआ। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों और अन्य विपक्षी नेताओं ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सरकार असहज सवालों से बचने के लिए विपक्ष को बोलने से रोक रही है और संसदीय नियमों का सहारा लेकर कार्रवाई कर रही है।

विवाद की जड़ में वही सवाल बना हुआ है कि राहुल गांधी को 2020 के भारत–चीन संघर्ष से जुड़े पूर्व सेना प्रमुख के लेख का हवाला देने से क्यों रोका गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर खुली चर्चा से बच रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन में केवल वही दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं, जिनकी अनुमति और प्रामाणिकता तय हो।

दिनभर चले इस घटनाक्रम ने संसद की कार्यवाही को लगभग ठप कर दिया। शोर-शराबे और टकराव के कारण कोई ठोस विधायी कामकाज नहीं हो सका। अंततः लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संसद में संवाद और बहस की परंपरा कमजोर पड़ती जा रही है और क्या राजनीतिक टकराव संसदीय मर्यादा पर भारी पड़ रहा है।

दवाइयों की कीमतों पर सवाल, मुनाफाखोरी के आरोपों से गरमाया संसद

जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में दवाइयों की बढ़ती कीमतों और फार्मा कंपनियों की कथित मुनाफाखोरी को लेकर एक बार फिर संसद में बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सदन में इस मुद्दे को मजबूती से उठाते हुए सरकार से सीधा सवाल किया कि आखिर ऐसी दवा कंपनियों पर लगाम कब लगेगी, जो आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाकर 600 से 1100 प्रतिशत तक मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज तथ्य हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। स्वाति मालीवाल ने कहा कि देश में दवाइयों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से लगातार बाहर होती जा रही हैं। बीमारी की हालत में किसी के पास मोलभाव का विकल्प नहीं होता। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा मरीज को हर हाल में खरीदनी पड़ती है और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ निजी फार्मा कंपनियां बेहिसाब मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक ही दवा जेनेरिक रूप में 80 से 90 प्रतिशत सस्ती उपलब्ध हो सकती है, तो सिर्फ ब्रांड के नाम पर कई गुना ज्यादा कीमत वसूलना किस तरह जायज ठहराया जा सकता है। राज्यसभा में सवाल उठाने के बाद स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर

भी इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा। उन्होंने लिखा कि कुछ प्राइवेट फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों पर 600 से 1000 प्रतिशत तक मुनाफा कमा रही हैं और यह बात खुद संसद की समिति की रिपोर्ट में दर्ज है। उन्होंने कहा कि ब्रांड के नाम पर जनता से की जा रही यह वसूली सीधे तौर पर शोषण की श्रेणी में आती है, क्योंकि मरीज के पास दवा न लेने का कोई विकल्प नहीं होता। अपने बयान को और स्पष्ट करते हुए स्वाति मालीवाल ने कुछ दवाओं के उदाहरण भी दिए। उन्होंने बताया कि सिट्रिजिन जैसी आम एलर्जी की दवा, जिसकी वास्तविक लागत करीब डेढ़ रुपये है, वही बाजार में 20 रुपये से अधिक कीमत पर बेची जा रही है। इसी तरह, दर्द निवारक आइबुप्रोफेन की लागत जहां कुछ सौ रुपये बताई जाती है, वहीं उसकी एमआरपी कई हजार रुपये तक पहुंच जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंसुलिन इंजेक्शन जैसे जीवनरक्षक दवाओं में 100 प्रतिशत से अधिक का प्राइस वेरिएशन देखने को मिलता है, जो बेहद चिंताजनक है।

स्वाति मालीवाल ने जोर देकर कहा कि मामला सिर्फ आम दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एंटीबायोटिक्स और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें तो लाखों रुपये तक पहुंच जाती हैं। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए इलाज कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कोई व्यापार नहीं, बल्कि हर नागरिक का मूल अधिकार है, और इसे मुनाफे का साधन बनाना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकता। सदन में बोलते हुए स्वाति मालीवाल ने सरकार से यह जानना चाहा कि क्या दवाइयों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कोई मजबूत और प्रभावी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब संसद की समिति खुद इस मुनाफाखोरी को स्वीकार कर रही है, तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह ठोस कदम उठाए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक आम आदमी की गाढ़ी कमाई कुछ चुनिंदा कंपनियों के मुनाफे में जाती रहेगी। इस मुद्दे ने स्वास्थ्य व्यवस्था और दवा नीति को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता के बावजूद ब्रांडेड दवाओं का दबदबा बना हुआ है। डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन, मार्केटिंग रणनीतियां और ब्रांड की विश्वसनीयता का हवाला देकर कंपनियां ऊंची कीमतें वसूलती हैं। वहीं, मरीज अक्सर यह नहीं जान पाते कि उसी दवा का सस्ता विकल्प भी बाजार में मौजूद है। स्वाति मालीवाल के इस बयान के बाद विपक्ष ने भी सरकार से जवाबदेही की मांग तेज कर दी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि दवाइयों की कीमत तय करने वाली मौजूदा व्यवस्था कितनी प्रभावी है और क्या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जैसी संस्थाएं इस मुनाफाखोरी को रोक पाने में सक्षम हैं। आलोचकों का कहना है कि जब तक दवाओं की कीमतों पर सख्त नियंत्रण और पारदर्शिता नहीं लाई जाती, तब तक आम जनता को राहत मिलना मुश्किल है। फिलहाल सरकार की ओर से इस मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, इस पर सबकी नजर है।

"मेरा टिकट, मेरी शान - विकसित भारत के लिए मेरा योगदान"

जन-जागरूकता अभियान में भावनगर की माननीय विधायक एवं महापौर की गरिमामयी सहभागिता

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेल यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा डिजिटल रेलवे सेवाओं के अधिकाधिक उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री तरूण जैन के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से संचालित "मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" अभियान के अंतर्गत दिनांक 03 फरवरी, 2026 (मंगलवार) को भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर एक प्रभावी जन-जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में भावनगर की माननीय विधायक श्रीमती सेजलबेन पंड्या, महापौर श्री भरतभाई बारड, उपमहापौर श्रीमती मोनाबेन पारेख, एम्बुलेंस 108 के हेड श्री कपिल सोलंकी, सौराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के श्री अशोक कोटाडिया सहित अन्य स्थानीय गणमान्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के महत्व से अवगत कराया और यह

संदेश दिया कि टिकट लेकर यात्रा करना केवल एक कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिकता का प्रतीक है। इस पहल के माध्यम से यात्रियों में जिम्मेदार एवं अनुशासित यात्रा की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

इस अवसर पर वाणिज्य विभाग द्वारा यात्रियों को रेलवन ऐप (RailOne App) की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ऐप के प्रमुख लाभों जैसे — आसान टिकट बुकिंग, ट्रेनों की रीयल-टाइम जानकारी तथा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न रेलवे सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया तथा यात्रियों को डिजिटल सेवाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह अभियान यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने, डिजिटल रेलवे सेवाओं को अपनाने तथा एक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल रेलवे प्रणाली के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी से अपील की है कि सभी यात्री उचित टिकट लेकर यात्रा करें और यह संदेश जन-जन तक पहुँचाएं।

इस अभियान से यात्रियों में रेलवे नियमों, नागरिक कर्तव्यों, ईमानदार यात्रा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का जिला कलेक्टरों से आह्वान- आगामी मानसून से पहले ही जल संचय के कार्यों का अग्रिम आयोजन कर बरसाती पानी के अधिकाधिक संचय और संग्रह के जरिए जल संचय के क्षेत्र में गुजरात का नेतृत्व बनाए रखें

मुख्यमंत्री ने राज्य में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान के कामकाज की सर्वग्राही समीक्षा के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह आह्वान किया

इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल और विभाग के सचिव श्री कांताराव और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारी दिल्ली से तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, मुख्य सचिव श्री एम. के. दास सहित वरिष्ठ सचिव गांधीनगर से शामिल हुए

जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान के कामकाज की सर्वग्राही समीक्षा के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में दिल्ली से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री वी.एल. कांताराव और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ गांधीनगर से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास और वरिष्ठ सचिव शामिल हुए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य के बनासकांठा, कच्छ और राजकोट जिले के कलेक्टरों के प्रेजेंटेशन सहित विभिन्न जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान की प्रगति और आगामी आयोजन की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और उनका समाधान देने का मार्गदर्शन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए 'कैच द रेन' अभियान और जल संचय की राष्ट्रव्यापी मुहिम का अधिक से अधिक लाभ गुजरात को मिले।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों को सीख देते हुए कहा कि वे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने जिलों में बरसाती पानी के संग्रहण और संचयन के कार्य करें। ये सभी ऐसे जनहित के कार्य हैं, जिनसे कर्तव्य निभाने के कार्य संतोष के साथ-साथ आत्मसंतोष भी मिलता है।

मुख्यमंत्री ने ऐसा वातावरण बनाने की हिमायत की जिसमें राज्य के जिलों के बीच जल संचय-जनभागीदारी अभियान के कार्यों को लेकर स्वस्थ

प्रतिस्पर्धा हो और जिन जिलों में जल संचय का काम कम हुआ हो, उन्हें भी अधिक कार्य करने का बल मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक को जल संचय-जल संग्रह के कार्यों के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान आवंटित किया है, इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करें कि इसका भी उपयोग जिलों में जल संचय के कार्यों के लिए हो।

मुख्यमंत्री ने बैठक में जल संचय के व्यापक कार्यों को तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया ताकि केंद्र सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी योजना के अंतर्गत राज्य को आवंटित 553 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता का संपूर्ण उपयोग मार्च-2026 से पहले हो जाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि जल संचय-जल संग्रह क्षेत्र में गुजरात ने जो कार्य किया है, वह देश में मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि पुराने बोर रिचार्ज करने की 70 फीसदी राशि केंद्र सरकार द्वारा देने के निर्णय से बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने जल संचय के कार्यों में अधिक संख्या में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जोड़ने के लिए एक सूची बनाकर उन्हें प्रेरित करने पर जोर दिया।

श्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लागू होने वाली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत मिलने वाले फंड का 40 फीसदी जल संचय-जल संग्रह के कार्यों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, ऐसा उदार प्रावधान किया गया है।

उन्होंने इस योजना के अंतर्गत समय पर और योजनाबद्ध तरीके से धन खर्च करने का मार्गदर्शन देते हुए कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से वाटर स्ट्रक्चर बनाकर जल संचय-जल संग्रह क्षमता में निरंतर वृद्धि से प्रधानमंत्री के जल सुरक्षा-जल आत्मनिर्भरता का संकल्प पूरा हो सकेगा।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चालू वर्ष में जल संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान के तहत आगामी 31 मई, 2026 तक देश भर में एक करोड़ से अधिक जल संग्राहक स्ट्रक्चर बनाने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए गुजरात में जल संचय के अधिकतम कार्य अगले मानसून से पहले पूर्ण करने का सुझाव दिया।

बैठक में इसकी भी समीक्षा की गई कि जल संचय जन भागीदारी 01 अभियान के तहत गुजरात में कुल 1,33,522 जल संचय के कार्य पूरे किए गए हैं तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ट्यूबवेल, तालाब गहरा करने, खेत तालाब और फिल्टर वेल जैसे जल संचय के कार्य होने से भूगर्भ जल रिचार्ज में बड़ा फायदा हुआ है।

मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने इस बैठक में जल संचय-जन भागीदारी अभियान 2.0 की उज्ज्वल सफलता के लिए सभी जिला कलेक्टरों को मिशन मोड में कार्यरत होने का सुझाव दिया।

समीक्षा बैठक में जलापूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, प्रधान सचिव श्री धनंजय द्विवेदी, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार तथा जल संसाधन सचिव श्री पी.सी. व्यास भी मौजूद रहे।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

समता के नाम पर असंतुलन: यूजीसी नियम, सुप्रीम कोर्ट की रोक और उच्च शिक्षा में न्याय का प्रश्न

उच्च शिक्षा किसी भी लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ होती है। यहीं से न केवल ज्ञान और कौशल का विकास होता है, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों की वास्तविक समझ भी आकार लेती है। इसी पृष्ठभूमि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 को देखा जाना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट था—उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, नस्ल या दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। मंशा पर सवाल नहीं है, सवाल उस ढांचे पर है, जिसे इन नियमों के जरिए खड़ा करने की कोशिश की गई और जो अंततः सुप्रीम कोर्ट की रोक का कारण बना।

इन नियमों के सामने आते ही विश्वविद्यालय परिसरों में असहजता फैल गई। विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों में यह आशंका गहराने लगी कि कहीं यह व्यवस्था उन्हें पहले से ही संदेह के घेरे में खड़ा न कर दे। किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक प्रणाली की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि वह निष्पक्ष दिखे भी और निष्पक्ष हो भी। यदि नियमों की बनावट ही ऐसी हो कि एक पक्ष खुद को असुरक्षित और पहले से दोषी महसूस करने लगे, तो वहां समता की भावना कमजोर पड़ने लगती है।

यूजीसी के इन नियमों की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि इनमें शिकायत की सत्यता जांचने के लिए स्पष्ट और मजबूत प्रक्रिया का अभाव दिखा। शिकायत मिलते ही समिति गठित कर त्वरित कार्रवाई का प्रावधान तो है, लेकिन यह साफ नहीं किया गया कि साक्ष्य किस मानक पर परखे जाएंगे, गवाहों को कैसे सुना जाएगा, गोपनीयता कैसे सुनिश्चित होगी और यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से आरोपित हो जाए तो उसके पास अपील या पुनरीक्षण का क्या अधिकार होगा। न्याय केवल त्वरित होने से नहीं होता, वह संतुलित और प्रक्रियागत रूप से सही होना चाहिए। जल्दबाजी में की गई कार्रवाई कई बार न्याय से ज्यादा अन्याय को जन्म देती है।

संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल भावना है कानून के समक्ष समानता। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, बल्कि यह भी कि किसी भी वर्ग के साथ बिना उचित कारण के भेदभाव न किया जाए। अनुच्छेद 15(1) जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यदि कोई नियम किसी खास सामाजिक समूह को संरक्षण देता है, लेकिन उसी प्रक्रिया में अन्य समूहों के अधिकारों की अनदेखी करता है, तो वह संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ देता है। अदालतें बार-बार यह कह चुकी हैं कि गरिमा, निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया तक पहुंच जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा हैं। ऐसे में यदि कोई छात्र या शिक्षक, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य आरक्षित श्रेणियों में नहीं आता, जाति आधारित भेदभाव का आरोप झेलता है या स्वयं भेदभाव का शिकार होता है, और उसके पास कानूनी संरक्षण या स्पष्ट उपाय नहीं हैं, तो यह प्रक्रियात्मक अन्याय की श्रेणी में आता है। यूजीसी के नियमों की आंतरिक विसंगतियां भी गंभीर चिंता का विषय हैं। एक ओर नियम-2 में वंचित समूहों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ धाराएं न्याय के अधिकार को सीमित दायरे में बांध देती हैं। यह विरोधाभास न केवल कानूनी अस्पष्टता पैदा करता है, बल्कि संस्थानों के लिए भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है कि वे इन नियमों को कैसे लागू करें। कानून की भाषा जितनी स्पष्ट होती है, उसका पालन उतना ही सहज होता है। अस्पष्टता हमेशा दुरुपयोग की गुंजाइश बढ़ाती है।

यह भी याद रखना जरूरी है कि फरवरी 2025 में जब इन नियमों का मसौदा सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया गया था, तब उसमें कुछ संतुलनकारी प्रावधान मौजूद थे। उस मसौदे में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को हतोत्साहित करने और आवश्यक होने पर जुर्माने का प्रावधान था। अंतिम अधिसूचित नियमों में इन प्रावधानों का हट जाना इस पूरी व्यवस्था को कमजोर बना गया। किसी भी शिकायत प्रणाली में यदि गलत शिकायतों के लिए कोई निवारक उपाय नहीं होता, तो उसका दुरुपयोग लगभग तय हो जाता है। इतिहास गवाह है कि अच्छे इरादों से बने कानून भी जब संतुलन खो देते हैं, तो वे समस्या का समाधान करने के बजाय नई समस्याएं खड़ी कर देते हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 बताता है कि उच्च शिक्षा में लगभग 60 प्रतिशत विद्यार्थी आरक्षित वर्ग से आते हैं। यह आंकड़ा सामाजिक समावेशन की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है, लेकिन साथ ही एक व्यावहारिक सवाल भी खड़ा करता है।

लोकलुभावन की बजाय आर्थिक सेहत ठीक करने वाला बजट

> “ विदेशी समाचार माध्यमों और समाचार एजेंसियों की नजर में यह बजट एक तरह से क्रांतिकारी है। दुनिया की जानी-मानी आर्थिक समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग का कहना है कि भारत ने अपने बजट में $133 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर दांव लगाया है। इसके जरिए भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुपरचार्ज करने की तैयारी में है।

अंग्रेजी में एक मुहावरा है, टू रॉब पीटर टू पे पॉल। हिंदी में इसका मतलब होगा, पीटर से लेकर पॉल को देना। दुनिया की हर सरकारों के बजट के लिए इस मुहावरे का बखूबी इस्तेमाल होता है। मीडिया भी हर बजट के दिन एक खबर जरूर बनाता है, रूपया आएगा कहां से और जाएगा कहां। इसका भी मतलब इस मुहावरे जैसा ही। बजट प्रबंधन में दुनियाभर की सरकारें एक व्यक्ति या स्रोत से लेकर दूसरे को उपलब्ध कराती रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बजट ऐसा ही होता है। लोकसभा में साल 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट को इस मुहावरे से कुछ हद तक दूर रखा जा सकता है। बजट प्रस्तावों की मीमांसा होती रहेगी, लेकिन फौरी तौर पर देखें तो कुछ चीजें साफ होती हैं। इस बजट के बारे में कह सकते हैं कि यह लोकलुभावन नहीं है। साल 2024-25 और 2025-26 के बजट को देखें तो उन दिनों मोदी सरकार पर जनता से किए गए वायदों को पूरा करने का दबाव था। इसलिए बीते दोनों बजट में लोकलुभावन घोषणाएं की गईं। वैसे भारतीय राजनीति की रवायत बन चुकी है कि ऐन चुनावों से पहले आने वाले बजट प्रस्तावों में उस राज्य विशेष जहां चुनाव होने हैं, के लिए लुभावनी घोषणाओं की बाढ़ आ जाती है। कुछ ही महीनों बाद पांच महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल पर बीजेपी जहां कब्जे की कोशिश में दिन-रात एक किए हुए हैं, वहीं प्रश्न प्रदेश बने तमिलनाडु में भी अपनी ताकतवर उपस्थिति जताने के लिए जोर लगाए हुई है। तमिलनाडु के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में भी चुनाव होने हैं। इसी तरह बीजेपी की कोशिश गॉड'स ओन कंट्री यानी भगवान के अपने घर केरल में कमल का फूल खिलाने की है। जबकि असम में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए मुतमइन है। राजनीतिक रवायत के मुताबिक, मौजूदा बजट प्रस्तावों में इन राज्यों के लिए घोषणाओं की बाढ़ आनी चाहिए थी। लेकिन तमिलनाडु से आने वाली निर्मला सीतारमण ने अपने नौंवे बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस लिहाज से यह बजट भारतीय राजनीति का नया चेहरा प्रस्तुत कर रहा है।

इस बजट के बारे में कहा जा सकता है कि यह लोकलुभावन घोषणाओं की बजाय संरचनात्मक सुधारों, विनिर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस बजट में जिस तरह शी मार्ट के जरिए महिला उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने की बात है, बेकार और अनुपयोगी हो चुके कानूनों को बदलने के लिए समिति बनाने का का प्रस्ताव है या सात हाईस्पीड रेल कॉरीडोर बनाने की बात है या फिर ग्रामीण बजट को बढ़ावा दिया गया है, या फिर मनरेगा की जगह पर आए नए कानून जी राम जी को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया गया है, उस वजह से यह बजट अलग स्वरूप लिए हुए दिख रहा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इसे वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को सशक्त बनाने वाला बजट बताया है। हालांकि पूर्व वित्त मंत्री और अर्थशास्त्री पी चिदंबरम् मानते हैं कि इस बजट प्रस्ताव में सरकार चीन और अमेरिकी दबाव में दिख रही है।

लेकिन विदेशी समाचार माध्यमों और समाचार एजेंसियों की नजर में यह बजट एक तरह से क्रांतिकारी है। दुनिया की जानी-मानी आर्थिक समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग का कहना है कि भारत ने अपने बजट में $133 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर दांव लगाया है। इसके जरिए भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुपरचार्ज करने की तैयारी में है। इसके साथ ही ब्लूमबर्ग ने बजट में 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स को ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बड़ा संकेत माना है। दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इन बजट प्रस्तावों को लेकर कहा है कि भारत के इस बजट में वित्तीय अनुशासन बनाम विकास का द्वंद्व दिख रहा है। एजेंसी कहती है कि बजट प्रस्ताव में मोदी सरकार ने 4.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। इसी तरह उसने बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया। मोदी सरकार के ये कदम नए बदलाव के प्रतीक हैं। ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध आर्थिक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने मोदी सरकार के बजट को लेकर कहा है कि यह ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत का स्थिर कदम है। इस बजट के जरिए भारतीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। दुनिया की जानी-मानी पत्रिका फोर्ब्स ने 2026 के बजटको लेकर एक तरह से हैरत जताते हुए सवाल पूछ लिया है कि क्या सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र मे निवेश भारत को टेक्निकल दुनिया का सुपरपावर बनाएगा? दुनिया की दूसरी बड़ी समाचार एजेंसी एएफपी ने भारत के बजट में बुनियादी ढांचे के लिए रिकॉर्ड 133 अरब डॉलर देने के वादे का स्वागत किया है। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं दूसरी संस्थाओं की भी है। मशहूर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस बजट को 'टैक्टिकल' यानी रणनीतिक करार दिया है। मूडीज का मानना है कि यह बजट क्रेडिट प्रोफाइल में तुरंत बदलाव नहीं करेगा, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए अच्छा है। इन प्रतिक्रियाओं में प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया को भी जोड़ सकते हैं, जिन्होंने इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया है। भारतीय मध्य वर्ग को हर बार बजट से बड़ी उम्मीद रहती है। देश का सबसे बड़ा आयकर दाता मध्य वर्ग ही है। उसे उम्मीद थी कि इस बार के बजट में आयकर पर किंचित ही सही, छूट मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे उसे थोड़ी निराशा तो जरूर हुई है। बीबीसी और अल जजीरा जैसे चैनलों ने इस मुद्दे को अपनी रवायत के मुताबिक अपनी समीक्षाओं में प्रमुखता दी है। दोनों ही समाचार संस्थानों ने भारतीय विपक्षी नेताओं और आर्थिक-तकनीकी विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि आयकर स्लैब में बदलाव न होने से मध्यम वर्ग को उतनी राहत नहीं मिली, जितनी उम्मीद थी। सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि आठवें वेतन आयोग को लेकर भी बजट में कोई बड़ी चर्चा या ऐलान हो सकता है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने इससे परहेज किया।

इसका यह मतलब नहीं कि बजट में आम आदमी का ध्यान नहीं रखा गया है। बजट में कुछ बेहतरीन घोषणाएं भी हुई हैं। महिला उत्थान और सशक्तीकरण की बात खूब की जाती है, लेकिन गांवों या छोटे शहरों से बड़े शहरों में पढ़ाई या नौकरी के लिए आने वाली लड़कियों की सहूलियतों पर कम ही ध्यान दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार बजट में उनका ध्यान रखा है। बजट में हर जिले में महिला छात्रावास बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बजट का यह फैसला लड़कियों को कॉलेज और नौकरियों तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। मां-बाप भी बिना किसी डर के सरकारी हास्टलों में अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज सकेंगे। इससे न केवल पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम होगी, बल्कि लड़कियां खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगी। पढ़ाई के साथ-साथ जो अपना छोटा-मोटा काम करने या स्टार्टअप चलाने वाली महिलाओं के लिए भी बजट में घोषणा हुई है। सरकार ने 'शी माट्‌र्स' नामक प्लेटफॉर्म शुरू करने का फैसला किया है। ये ऐसे बाजार या प्लेटफॉर्म होंगे, जहां सिर्फ महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और महिला कारीगर ही अपना सामान बेच सकेंगी। इससे महिलाओं को बिचौलियों की जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरह कैंसर के इलाज वाली 17 दवाओं के साथ ही शुगर की दवाओं पर कर में कमी की गई है। साथ ही सात दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से आयात होने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन्हें बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। भारत को बायोफार्मा का हब बनाने का भी ऐलान किया गया है। ग्रामीण विकास पर दो लाख 73 हजार 108 करोड़ और कृषि एवं कृषि विकास पर एक लाख 62 हजार 671 करोड़ के बजट का प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों की रौनक बढ़ा सकता है।

प्रेरणा

स्वर्ग और नरकः इंसान के भीतर रचा हुआ संसार

अक्सर जब स्वर्ग और नरक की बात होती है तो हमारी कल्पना किसी अदृश्य लोक की ओर चली जाती है। हमें लगता है कि यह सब मृत्यु के बाद घटित होगा, किसी दूसरे संसार में, जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब लगाया जाएगा। लेकिन सूफी दर्शन इस सोच को बहुत सहज ढंग से उलट देता है। वह कहता है कि स्वर्ग और नरक कोई दूर की जगहें नहीं हैं, बल्कि मनुष्य के जीवन की अवस्थाएँ हैं, जो इसी धरती पर, इसी समय अनुभव की जाती हैं। इंसान जैसा जीवन जीता है, जैसा सोचता है, जैसा कर्म करता है, वही उसका स्वर्ग और वही उसका नरक बन जाता है।

एक सूफी संत से कुछ लोगों ने यही सवाल किया था कि आखिर जन्नत और दोज़ख़ क्या है। संत ने न तो कोई दार्शनिक परिभाषा दी और न ही किसी किताब का हवाला दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि कल उनके साथ चलो, उत्तर खुद दिखाई देगा। अगले दिन वे लोग संत के साथ निकले। पहली जगह जहाँ वे पहुँचे, वह एक शिकारी का घर था। शिकारी अपने शिकार के साथ लौटा था। मरे हुए जानवर, खून और हिंसा उसके जीवन का हिस्सा थे। सूफी संत ने उस दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही दोज़ख़ है। जो व्यक्ति जीवन भर निर्दयता से जीता है, वह चाहे बाहर से कितना ही शक्तिशाली क्यों न दिखे, भीतर से वह हमेशा भय, क्रूरता और अशांति में जलता रहता है।

यह बात केवल जंगल के शिकारी तक सीमित नहीं है। आधुनिक समाज में भी ऐसे असंख्य शिकारी हैं, जो दूसरों का शोषण करते हैं, झूठ और छल से आगे बढ़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वे बड़े घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन उनका मन कभी शांत नहीं होता। उन्हें हर समय डर रहता है—डर कि कहीं उनका झूठ उजागर न हो जाए, डर कि कहीं उनसे बड़ा शिकारी न आ जाए। यही डर, यही बेचैनी उनका नरक बन जाती है। यह नरक आग और धुएँ से नहीं, बल्कि अंतहीन असंतोष से बना होता है।

इसके बाद सूफी संत लोगों को जंगल में रहने वाले एक फ़क़ीर के पास ले गए। वह व्यक्ति एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके पास न धन था, न ऐश्वर्य, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। उसकी आँखों में संतोष और शांति झलक रही थी। वह प्रकृति के साथ तालमेल में जी रहा था। सूफी संत ने कहा कि इस व्यक्ति ने आने वाले सुख के लिए आज के लालच को छोड़ दिया है। इसने इच्छाओं की आग को शांत कर लिया है, इसलिए इसके लिए जन्नत निश्चित है। यह जन्नत कोई भोग-विलास से भरा स्वर्ग नहीं है, बल्कि मन की वह अवस्था है जहाँ इच्छाएँ इंसान को नहीं चलातीं। फ़क़ीर का जीवन यह सिखाता है कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की तृप्ति में है। जब मन को यह समझ आ जाती है कि जितना है, वही पर्याप्त है, तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। भूख, नींद, मेहनत और विश्राम—सब कुछ संतुलन में आ जाता है। यही संतुलन स्वर्ग की पहली सीढ़ी है।

लेकिन सूफी संत यहीं नहीं रुके। तीसरी जगह वे एक साधारण गृहस्थ के घर पहुँचे। वह न तो शिकारी था और न ही फ़क़ीर। वह रोज़ मेहनत करता था, ईमानदारी से कमाता था और अपने परिवार के साथ सादगी से जीवन जीता था। उसके घर में प्रेम था, आपसी सम्मान था, और दूसरों के लिए मदद की भावना थी। वहाँ न कोई दिखावा था और न ही अभाव का रोना। सूफी संत ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में भी जन्नत है और उस दुनिया में भी जन्नत। यह बात बहुत गहरी है। यह बताती है कि अध्यात्म का मतलब संसार छोड़ देना नहीं है। न ही इसका अर्थ केवल त्याग और तपस्या है। असली अध्यात्म उस जीवन में है, जहाँ इंसान अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अपने भीतर इंसानियत को जीवित रखता है। जब परिवार में प्रेम होता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है और मन में ईमानदारी होती है, तब साधारण सा घर भी स्वर्ग बन जाता है।

सूफी दर्शन हमें यह सिखाता है कि स्वर्ग और नरक किसी धर्म विशेष की अवधारणा नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव हैं। जब इंसान क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लालच में जीता है, तो वह हर दिन नरक की आग में जलता है। उसका मन अशांत रहता है, रिश्ते टूटते हैं और जीवन बोझ बन जाता है। इसके विपरीत, जब वही इंसान प्रेम, करुणा, क्षमा और संतोष को अपनाता है, तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, उसे भीतर से शांति मिलती है। यही शांति स्वर्ग है।

आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में यह संदेश और भी ज़रूरी हो जाता है। लोग हर पल किसी न किसी दौड़ में शामिल हैं। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा नाम, ज़्यादा ताकत—इन सबके पीछे भागते हुए वे अपने जीवन का असली सुख खोते जा रहे हैं। बाहर से चमकदार दिखने वाली यह जिंदगी भीतर से खोखली हो जाती है। यही आधुनिक नरक है, जहाँ इंसान सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पा पाता।

इसके उलट, जो लोग सीमित साधनों में भी संतोष और सेवा का जीवन जीते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा लेते हैं। उनका मन स्थिर रहता है। वे जानते हैं कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं, देने का भी नाम है। जब इंसान किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनता है, तो वही पल उसके लिए स्वर्ग बन जाता है।

सूफी संत की यह कथा हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। क्या हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, या अपने भीतर की मानवता को बचाए रखे हुए हैं। क्योंकि स्वर्ग और नरक का फैसला कोई और नहीं करता, यह फैसला हम खुद अपने कर्मों से करते हैं।

अंत में यही कहा जा सकता है कि स्वर्ग और नरक कोई भविष्य की घटना नहीं हैं, वे वर्तमान की सच्चाई हैं। जो इंसान आज जैसे विचार, जैसे कर्म और जैसे संबंध बनाता है, वही उसकी दुनिया बन जाती है। अगर मन शुद्ध है, हृदय में प्रेम है और कर्म में ईमानदारी है, तो यही धरती स्वर्ग बन जाती है। और अगर जीवन घृणा, हिंसा और लालच से भरा है, तो यही धरती नरक में बदल जाती है। सूफी संत का संदेश सरल है—स्वर्ग और नरक को खोजने कहीं दूर मत जाओ, अपने भीतर झाँको, वहीं तुम्हें दोनों के दर्शन हो जाएंगे।

शिक्षा के जरिये रोजगार सृजन की दिशा में कदम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 को सरकार 'नेक्स्ट जेनरेशन बजट' कह रही है। यह दावा केवल एक राजनीतिक नारा नहीं लगता, बल्कि बजट के प्रावधानों पर नज़र डालने से स्पष्ट होता है कि इसमें जेनरेशन जेड- यानी आज के युवा वर्ग- की शिक्षा, रोजगार, तकनीकी कौशल और रचनात्मक आकांक्षाओं को केंद्र में रखा गया है। आज का युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं है; वह स्किल-ड्रिवन, डिजिटल-नेटिव और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बजट 2026-27 इसी बदले हुए युवा चरित्र को पहचानता है।

इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पर ज़ोर। सरकार ने शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक समग्र रणनीति अपनाई है। कौशल-आधारित शिक्षा, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों को बढ़ावा और यूनिवर्सिटी टाउनशिप की अवधारणा इस दिशा में अहम कदम हैं। महत्वपूर्ण है कि केवल डिग्रियां युवाओं को रोजगार नहीं दिला सकतीं; उन्हें व्यावहारिक कौशल और उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यदि यह योजना ज़मीनी स्तर पर सही ढंग से लागू होती है तो यह भारत की युवा बेरोज़गारी की समस्या को कम करने में निर्णायक साबित हो सकती है। विदेश में पढ़ाई-लिखाई करने वाले छात्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव चाहने वालों को राहत देने के लिए, सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। इससे विद्यार्थी विदेश शिक्षा-अनुभव को अधिक किफ़ायती रूप से चुन सकेंगे, जिससे तकनीकी तथा ग्लोबल मौके और एक्सपोज़र मिलेंगे।

बजट में ऑरेंज इकोनॉमी यानी एनिमेशन, गेमिंग, डिज़ाइन, विजुअल इफेक्ट्स और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देना जेन जेड के लिए एक बड़ा संदेश है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव इस बात का संकेत है कि सरकार अब यूट्यूब, गेमिंग, एनीमेशन और डिजिटल स्टोरीटेलिंग को शौक नहीं, बल्कि कैरियर के रूप में देख रही है। इस कदम का व्यापक लक्ष्य यह है कि भारत 2030 तक लगभग 20 लाख एवीजीसी सेक्टर-विशेषज्ञों की आवश्यकता को पूरा करे, और उसे विश्व-स्तर के डिजिटल क्रिएटिव हब में बदल दे। यह कदम भारत के लाखों क्रिएटिव युवाओं को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग पर दिया गया ज़ोर इस बजट को भविष्य-उन्मुख बनाता है। आज की नौकरियां डेटा, एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम्स से जुड़ी हैं। बजट यह मानता है कि अगर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहना है, तो युवाओं को इन्हीं क्षेत्रों में दक्ष बनाना होगा।

जेन जेड केवल नौकरी चाहने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि जॉब क्रिएटर बनने की आकांक्षा भी रखती है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से नए अवसर पैदा होंगे। इससे युवा उद्यमियों को जोखिम लेने और नवाचार करने का भरोसा मिलेगा। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस)में कमी यह दर्शाती है कि सरकार वैश्विक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज़र को भी महत्व दे रही है। यह फैसला मध्यम वर्गीय युवाओं के लिए विशेष रूप से राहतकारी है। भारत का युवा वर्ग पहले से ही स्टार्टअप और नवोन्मेष (इनोवेशन) की ओर अग्रसर है —यह बजट इन्हें संसाधन-समर्थक वातावरण देने की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। बजट ने खेलो इंडिया मिशन तथा खेल-इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार से युवाओं के खेल-प्रतिभा विकास को बढ़ावा दिया है। साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र की डिजिटलाइजेशन तथा पर्यटन-संबंधित कौशल विकास योजनाएं भी युवा रोजगार सृजन को आगे बढ़ाती हैं।

कुल मिलाकर, बजट 2026–27 केवल आज की जरूरतों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि आने वाले भारत की युवा-आधारित आर्थिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बजट जेन जेड को बोझ नहीं, बल्कि भागीदार मानता है। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित योजनाएं काग़ज़ से निकलकर ज़मीन तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं। यदि क्रियान्वयन मजबूत रहा तो यह बजट सचमुच भारत की अगली पीढ़ी को आत्मनिर्भर, कुशल और ग्लोबल नागरिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।

यह बजट शिक्षा से रोजगार तक का एकीकृत मार्ग प्रदान करता है। डिजिटल और तकनीकी कौशल को मुख्यधारा में लाता है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था और ऑरेंज इकोनॉमी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाता है। वैश्विक शिक्षा-अनुभव और रोजगार-सृजन के अवसरों को बढ़ाता है। यह बजट केवल आज के युवाओं के लिए नहीं बल्कि अगले पांच दशक के युवाओं के लिए एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार कर सकता है। साथ ही भारत को एक ग्लोबल तकनीकी-रचनात्मक शक्ति बनाने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम प्रतीत होता है।

अभियान

माँ की गोद में बँधा ईश्वर: वात्सल्य की वह पराकाष्ठा जहाँ अनंत भी सीमित हो गया

सनातन परंपरा में यदि किसी भाव को ईश्वर के सर्वाधिक निकट माना गया है, तो वह है वात्सल्य। यह वह प्रेम है जिसमें न आराधना की भाषा होती है, न उपासना की विधि, न ही किसी फल की कामना। वात्सल्य वह भाव है जिसमें माँ अपने अस्तित्व को भूलकर केवल अपने बच्चे के अस्तित्व में जीती है। इसी भाव की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माता यशोदा और भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में प्रकट होती है। यह संबंध न केवल पौराणिक कथा है, न केवल धार्मिक आस्था, बल्कि भक्ति-दर्शन का वह शिखर है जहाँ ईश्वर स्वयं अपने ऐश्वर्य को त्यागकर प्रेम के अधीन हो जाता है।

भगवान श्रीकृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ, किंतु जन्म और मातृत्व में अंतर है। देवकी ने भगवान को जन्म दिया, परंतु यशोदा ने उन्हें जीवन दिया। देवकी ने उन्हें गर्भ में धारण किया, यशोदा ने उन्हें अपने हृदय में धारण किया। देवकी ने उन्हें भय के बीच जन्म दिया, यशोदा ने उन्हें निर्भय होकर पाला। यही कारण है कि शास्त्रों में देवकी को 'जननी' कहा गया और यशोदा को 'माता'। यह अंतर केवल शब्दों का नहीं, भावों का है।

यशोदा के लिए कृष्ण कभी 'भगवान' नहीं थे। यही उनकी सबसे बड़ी साधना थी। यदि उन्हें यह ज्ञान हो जाता कि उनका पुत्र स्वयं परब्रह्म है, तो उनका वात्सल्य नष्ट हो जाता। इसलिए भगवान ने स्वयं अपनी योगमाया से उन्हें इस ज्ञान से दूर रखा। यही कारण है कि जब ब्रह्माण्ड का दर्शन कराने वाले कृष्ण उनके सामने खड़े होते हैं, तब भी यशोदा उन्हें केवल अपना लल्ला मानती हैं। उनके लिए कृष्ण की शक्ति नहीं, उनकी भूख महत्वपूर्ण थी; उनका ऐश्वर्य नहीं, उनका रोना महत्वपूर्ण था।

ब्रज की धरती पर घटित प्रत्येक लीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक संकेत है। जब कृष्ण माखन चुराते हैं, तो वह केवल बालसुलभ शरारत नहीं है। माखन शुद्ध प्रेम का प्रतीक है, और कृष्ण वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम छुपाकर रखा जाता है। जब यशोदा उन्हें पकड़ती हैं, डाँटती हैं, तब वह ईश्वर को दंड नहीं दे रहीं, बल्कि एक माँ अपने पुत्र को अनुशासन सिखा रही है। यही वह बिंदु है जहाँ भक्त और भगवान का संबंध उलट जाता है—यहाँ भगवान निर्भर हैं, भक्त स्वामी है। दामोदर लीला इसी वात्सल्य का चरम है। जब यशोदा कृष्ण को ओखल से बाँधने का प्रयास करती हैं और हर बार रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ जाती है, तब यह लीला केवल चमत्कार नहीं रहती, बल्कि दर्शन बन जाती है। वे दो अंगुल—एक भक्त का पुरुषार्थ और एक भगवान की कृपा—भक्ति के संपूर्ण सिद्धांत को समेटे हुए हैं। जब तक दोनों नहीं मिलते, ईश्वर नहीं बंधते। और जब यशोदा थक जाती हैं, जब उनके नेत्रों में आँसू और हृदय में करुणा भर जाती है, तब वही अनंत स्वयं बंध जाता है।

यह दृश्य संसार के सभी दर्शन, सभी धर्मों और सभी शक्तियों को चुनौती देता है। यहाँ न तपस्या है, न योग, न ज्ञान—केवल प्रेम है। ऐसा प्रेम जो कुछ माँगता नहीं, केवल देता है। ऐसा प्रेम जो ईश्वर को भी छोटा बना देता है, बिना उनका अपमान किए।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यशोदा कोई साधारण आत्मा नहीं थीं। पूर्व जन्म में वे 'धरा' थीं और नंद बाबा 'वसुश्रेष्ठ द्रोण'। दोनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वर माँगने को कहा, तब उन्होंने न स्वर्ग माँगा, न मोक्ष, न ऐश्वर्य। उन्होंने केवल यही माँगा कि पृथ्वी पर जन्म लेने पर भगवान श्रीकृष्ण में उनकी अविचल भक्ति बनी रहे। यही वरदान आगे चलकर वात्सल्य में परिणत हुआ।

एक अन्य कथा बताती है कि यशोदा ने स्वयं भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। भगवान ने उन्हें वर दिया कि वे देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, पर मातृत्व का रस यशोदा को ही मिलेगा। यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं तय करते हैं कि वे किसके प्रेम के अधीन होंगे। शक्ति से नहीं, अधिकार से नहीं—केवल प्रेम से। भागवत पुराण में यशोदा को वात्सल्य रस की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। भक्ति के नौ रसों में वात्सल्य सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इसमें भक्त स्वयं को भगवान से बड़ा मानता है। वह भगवान की रक्षा करता है, उनकी चिंता करता है, उनके लिए भयभीत होता है। यह भाव तभी संभव है, जब अहंकार पूर्णतः समाप्त हो चुका हो।

यह भी कहा गया है कि वैकुण्ठ धाम में एक नित्य यशोदा हैं, जो भगवान की शाश्वत माता हैं। जब ब्रज में भगवान का अवतरण हुआ, तब वही नित्य यशोदा ब्रज की यशोदा में आविष्ट हो गईं। इस प्रकार लौकिक और अलौकिक यशोदा एक हो गईं। यही कारण है कि ब्रजलीला केवल पृथ्वी की कथा नहीं, बल्कि नित्य लीला का प्रतिबिंब है।

यशोदा नाम स्वयं में साधना है। 'यश' और 'दा'—जो दूसरों को यश दे। यशोदा ने कभी अपने लिए श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कृष्ण की किसी लीला का प्रचार नहीं किया। उनका जीवन मौन सेवा, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। यही कारण है कि भगवान स्वयं उनके चरणों में बंध गए।

आज के युग में, जहाँ संबंध लेन-देन पर आधारित हो गए हैं, माता यशोदा का चरित्र एक मौन प्रश्न बनकर खड़ा होता है—क्या हम बिना शर्त प्रेम करना जानते हैं? क्या हम किसी को केवल इसलिए चाहते हैं कि वह हमारा है, न कि इसलिए कि वह हमें कुछ देता है? माता यशोदा का वात्सल्य यही सिखाता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल और सबसे कठिन मार्ग प्रेम है। सरल इसलिए कि इसमें कोई विधि नहीं, और कठिन इसलिए कि इसमें स्वयं को मिटाना पड़ता है। जब अनंत स्वयं को माँ की गोद में सौंप देता है, तब यह सिद्ध हो जाता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री का ग्रामीण स्तर पर अधिक पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही के साथ विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम का कर्तव्य निभाने का सरपंचों से आह्वान

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी की अध्यक्षता में गणेश वासुदेव मावळंकर संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के उपक्रम में गुजरात विधानसभा सचिवालय में 'ग्राम शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम' का शुभारंभ

▸▸ उत्तर गुजरात के 7 जिलों की विभिन्न तहसीलों के 260 से अधिक गांवों के सरपंच सहभागी हुए

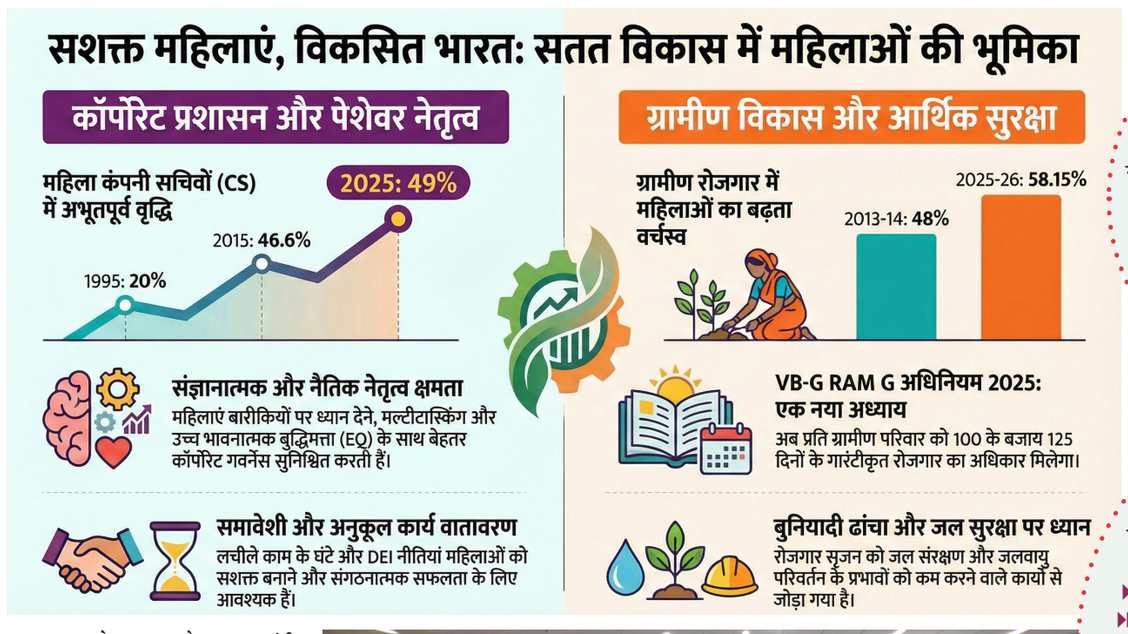

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को ग्राम पंचायतों के सरपंचों को ग्रामीण स्तर पर अधिक पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही के साथ विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम का कर्तव्य निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस वर्ष का केंद्रीय बजट भी कर्तव्य को मुख्य आधार बनाकर तैयार किया गया है, इतना ही नहीं इस बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश के विकास में गांवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरपंचों को गांव के मुखिया के रूप में जिम्मेदारीपूर्वक कर्तव्य निभाकर विकसित भारत के निर्माण में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र से जनशक्ति को जोड़ने का प्रेरक मार्गदर्शन दिया।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी तथा मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल एवं श्री कुंवरजीभाई बावळिया की उपस्थिति में गुजरात विधानसभा में गणेश वासुदेव मावळंकर संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के उपक्रम में 'ग्राम शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम' का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर गुजरात के बनासकांठा, वाव-थराद, मेहसाणा, पाटण, साबरकांठा और अरवल्ली जिलों की विभिन्न तहसील के 260 से अधिक सरपंच सहभागी हुए। गांवों को भारत की आत्मा कहा जाता है; इस भावना को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गांव के सभी लोग एक साथ विकास कार्यों में जुड़ते हैं, तब गांव का विकास चमक उठता है।

मुख्यमंत्री ने प्रेरणा देते हुए कहा कि सरपंच के रूप में मिली सेवा के अवसर को अपनी लगन और गांव के विकास के लिए कुछ बेहतर करने की भावना से योजनाबद्ध रूप से विकास कार्यों की सूची बनाकर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सेचुरेशन अप्रोच से 100 प्रतिशत लक्ष्य के साथ अनुदान का उपयोग हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरपंचों की प्राथमिक जिम्मेदारी गांव के सुदूरवर्ती व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है। जब गांवों का विकास होगा, तभी देश का वास्तविक विकास होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के जनहित के कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गांव के विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर टेक्नोलॉजी के उपयोग से नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना सरपंचों की जिम्मेदारी है।

किसी भी संकट की घड़ी में सरकार हमेशा उनके साथ है; यह आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने सरपंचों से आह्वान किया कि वे निश्चिंत होकर पूरी निष्ठा से जनसेवा के कार्य करें। उन्होंने सभी को साथ लेकर विकसित गांव से विकसित गुजरात और विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण की मंशा व्यक्त की।

गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई

विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी

▸▸ प्रधानमंत्री के 'ग्राम सचिवालय' के मंत्र को साकार कर गांवों को आधुनिक बनाने की जिम्मेदारी सरपंच की है

▸▸ पंचायत अधिनियम में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को जानकर गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरपंचों को अधिक कार्य करना चाहिए

▸▸ लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा में जनभागीदारी अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कर्तव्य के मुख्य आधार को लेकर प्रस्तुत किए गए बजट में ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया है

▸▸ देश के विकास की नींव में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका

▸▸ सरपंच गांव के मुखिया के रूप में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ जिम्मेदारीपूर्वक अपना कर्तव्य निभाकर विकसित भारत के निर्माण में ग्रामीण जनशक्ति को जोड़ें

▸▸ जनहित के कार्यों में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा

▸▸ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सेचुरेशन अप्रोच से 100 प्रतिशत लक्ष्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से अनुदान का उपयोग हो

गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने 'ग्राम शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम' में उपस्थित राज्य के कर्मठ सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया 'ग्राम सचिवालय' का मंत्र गांवों के विकास को नई दिशा देने वाला है। इस मंत्र को ग्रामीण स्तर पर साकार करने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की मुख्य जिम्मेदारी आप सभी सरपंचों की है।

अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने मुख्यमंत्री के सफल नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की परिकल्पना से ही आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम साकार हुआ है। राज्य सरकार गांवों के नागरिकों तक शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरपंचों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास केवल ईंट और सीमेंट के निर्माण से नहीं होता, विकास 'संवाद' से होता है। कई बार ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच संवाद की कमी से टकराव होता है। यदि गांव के छोटे से छोटे कार्य में भी ग्राम जनों को विश्वास में लेकर संवाद बढ़ाया जाए, तो संघर्ष स्वतः कम हो जाएगा और जनभागीदारी से गांव का वास्तविक विकास होगा। पंचायती राज के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत अधिनियम में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को समझकर गांव के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना ही सच्ची लोक सेवा है। लोकतंत्र में पंचायत से लेकर संसद तक वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन गांव के हित को सर्वोपरि रखते हुए विपक्ष की अच्छी बातों को भी संवाद के माध्यम से स्वीकार करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि पंचायत लोकतंत्र की नींव है। यदि यह नींव मजबूत होगी, तभी प्रधानमंत्री का 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा। उन्होंने सभी सरपंचों से गांवों को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाकर 'विकसित गुजरात' के माध्यम से 'विकसित भारत' के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया गया।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्राम गृह निर्माण मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल ने कहा कि ग्रामीण नागरिकों को शहर की कल्पना से जोड़ने तथा शहर जैसी सुविधाएं गांव में प्रदान कर एक 'आदर्श' गांव बनाने का भगीरथ कार्य आप सभी सरपंचों को करना है। हमारे श्री नरेन्द्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने गांव विकास के हित में 70 प्रतिशत राशि पंचायत की ग्रांट में से उपयोग करने का अधिकार सरपंच को देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जिससे सरपंच और ग्राम जन मिलकर विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर शहरों के समकक्ष गांवों में सुविधाएं प्रदान कर सकें। गांव के सरपंच ग्रामवासियों के साथ मिलकर यह तय कर सकते हैं कि गांव में कहां सड़क बनानी है, कहां पानी की व्यवस्था बाकी है, कहां लाइट और कहां नाली की सुविधा शेष है। इन सभी सुविधाओं को गांव के हितों को ध्यान में रखकर सरपंच ग्रांट प्रदान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त श्री ऋषिकेशभाई पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में आज गुजरात के सभी गांवों को कम से कम दो मार्गों से 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना' अंतर्गत जोड़ा गया है। श्री ऋषिकेशभाई पटेल ने कहा कि ग्राम शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी को गांव के प्रशासनिक शिक्षा के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। गांव में सरपंच का पद प्रमुख होता है, इसलिए आप सभी सरपंचों से निवेदन है कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ गांव के वृद्धों, विधवा महिलाओं तथा गांव के उन नागरिकों को, जिन्हें अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिली है, उन्हें सेवाओं का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी आप सभी सरपंचों की है।

ग्राम विकास मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावलळिया ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के निर्णयों के परिणामस्वरूप गांवों में शहरों के समकक्ष सुविधाएं मिल रही हैं। गांवों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सीधे ग्राम पंचायत के खाते में राशि दी जाती है। इस राशि का सही दिशा में उपयोग करने से गांव को गोकुल जैसा विकसित गांव बनाया जा सकता है। ग्राम विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख रुपए थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने 50 हजार रुपए की वृद्धि की है। यानी कि आगामी दिनों में गांव के नागरिकों को अपना घर बनाने के लिए1.70 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसके अलावा नागरिकों को मनरेगा योजना से शौचालय की सुविधा के लिए 5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। इस प्रकार गांव के प्रत्येक नागरिक को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना घर मिले तथा लोक उपयोगी योजनाओं का लाभ गांव के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सरपंच से अनुरोध किया।

इस अवसर पर विधानसभा सचिव श्री चेतन पंड्या ने स्वागत भाषण देकर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री बालकृष्ण शुक्ल ने आभार विधि की।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सरपंचों को संसदीय लोकतंत्र में पंचायत की भूमिका, जी-रामजी (जी-आरएएमजीआई) ग्राम विकास योजना, पंचायत लेखा नियम तथा ग्राम सभा में सरपंच के अधिकार और कर्तव्यों जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर विकास आयुक्त श्री हितेश कोया, विधानसभा के संयुक्त सचिव श्री रीटा मेहता, उप विकास अधिकारी तथा सरपंच उपस्थित रहे।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में गुजरात की विशेष उपलब्धि

हैदराबाद में आयोजित 'विंग्स इंडिया 2026' में गुजरात को मिला 'बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम' का पुरस्कार

जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात ने अन्य क्षेत्रों की तरह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी विशेष उपलब्धि हासिल की है। 28 से 31 जनवरी, 2026 के दौरान हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित 'विंग्स इंडिया 2026' सम्मेलन में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री के. राममोहन नायडू ने गुजरात को 'बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ सिविल एविएशन इकोसिस्टम' के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है, यह जानकारी गुजरात के नागर विमानन आयुक्त श्री के. एल. बचाणी ने दी।

गुजरात के नागर विमानन आयुक्त श्री बचाणी ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री के करकमलों से दिया गया यह पुरस्कार गुजरात की उड्डयन क्षेत्र की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं तथा एयरक्राफ्ट लीजिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। गुजरात के साथ ही तेलंगाना और उत्तराखंड भी इस श्रेणी में संयुक्त रूप से विजेता रहे।

इसके अलावा, नागर विमानन आयुक्त ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात के विमानन क्षेत्र को आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बनाने और अंतिम व्यक्ति तक हवाई कनेक्टिविटी पहुंचाने की राज्य सरकार की दूरदर्शिता को समर्पित है। यह सम्मान विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित करने और हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए और भी सुलभ बनाने की गुजरात की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुजरात को 'विंग्स इंडिया 2022' में 'बेस्ट स्टेट विद ए डेडिकेटेड आउटलुक फॉर द सेक्टर' तथा 'विंग्स इंडिया 2024' में 'बेस्ट स्टेट विद ए डेडिकेटेड लुकआउट फॉर एविएशन सेक्टर' का अवॉर्ड भी मिल चुका है।

पश्चिम रेलवे के 70वें रेल सप्ताह समारोह में भावनगर मंडल के 5 कर्मचारियों को मिला "विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार"

जीएनएस)। मुंबई स्थित यशवंतराव चव्हाण सभागार में सोमवार, 02 फरवरी 2026 को पश्चिम रेलवे के 70वें रेल सप्ताह समारोह के अंतर्गत विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (VRSP)–2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) श्री प्रदीप कुमार ने पश्चिम रेलवे के 92 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस प्रतिष्ठित समारोह में भावनगर मंडल के 5 कर्मचारियों को उनके अनुकरणीय कार्य, समर्पण एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है,

जिसका उद्देश्य पश्चिम रेलवे के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता एवं समर्पण को सम्मानित करना है, जो निरंतर चुनौतियों का सामना करते हुए संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। यह पुरस्कार न केवल सम्मान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनता है। भावनगर मंडल से सम्मानित कर्मचारी:

1.श्री लल्लन प्रसाद वर्मा – ट्रैक मेंटेनर
2.श्री दिनेश कुमार – प्वाइंट्समैन
3.श्री जिंजाला जगदिश मनसुखभाई – मुख्य वाणिज्य निरीक्षक (LSG & NFR)
4.श्री मोहम्मद हनिफ खान – सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट
5.श्री पिन्टु कुमार – टेक्नीशियन

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के कारण निरंतर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है और भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ प्रगति करता रहेगा।

सोना वायदा में 7307 रुपये और चांदी वायदा में 29116 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 6 रुपये फिसला

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 149830.46 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 55540.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 94285.73 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 38401 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3597.84 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 44352.45 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 145943 रुपये के भाव पर खूलकर, 150000 रुपये के दिन के उच्च और 145943 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 141693 रुपये के पिछले बंद के सामने 7307 रुपये या 5.16 फीसदी की मजबूती के साथ 149000 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 6356 रुपये या 5.37 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 124663 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 863 रुपये या 5.86 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15581 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 143389 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 150710 रुपये और नीचे में 142671 रुपये पर पहुंचकर, 8054 रुपये या 5.71 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 149155 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 146681 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 155300 रुपये और नीचे में 146681 रुपये पर पहुंचकर, 144296 रुपये के पिछले बंद के सामने 9101 रुपये या 6.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 153397 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 245711 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 270398 रुपये और नीचे में 245711 रुपये पर पहुंचकर, 236261 रुपये के पिछले बंद के सामने 29116 रुपये या 12.32 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 265377 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 29051 रुपये या 11.94 फीसदी की बढ़त के साथ 272277 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 29386 रुपये या 12.1 फीसदी की तेजी के संग 272229 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। मेटल वर्ग में 8287.12 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 60.2 रुपये या 4.94 फीसदी की तेजी के संग 1279.15 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1 रुपये या 0.31 फीसदी औंधकर 324 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 1.85 रुपये या 0.59 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 313.55 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी की नरमी के साथ 192.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कमोडिटी वायदाओं में 55540.87 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 94285.73 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 44352.45 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38401 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2701.92 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5607 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5637 रुपये और नीचे में 5515 रुपये पर पहुंचकर, 6 रुपये या 0.11 फीसदी घटकर 5619 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 14 रुपये या 0.25 फीसदी लुढ़ककर 5618 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 300 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 300 रुपये और नीचे में 286.5 रुपये पर पहुंचकर, 294.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 80 पैसे या 0.27 फीसदी की नरमी के साथ 294.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 80 पैसे या 0.27 फीसदी की नरमी के साथ 294.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 995 रुपये पर खूलकर, 5.8 रुपये या 0.59 फीसदी बढ़कर 984 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 28126.45 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 16225.99 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 6963.15 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 519.26 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 56.52 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 737.79 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 750.28 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1937.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 7.37 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9838 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 84404 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27663 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 378698 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 43721 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8908 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22105 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 63236 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15373 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 15402 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 37267 पॉइंट पर खूलकर, 38602 के उच्च और 37056 के नीचले स्तर को छूकर, 2219 पॉइंट बढ़कर 38401 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 7.3 रुपये की गिरावट के साथ 215.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 90 पैसे की नरमी के साथ 25.5 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2832.5 रुपये की बढ़त के साथ 11021.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5760.5 रुपये की बढ़त के साथ 18316.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 20.51 रुपये की बढ़त के साथ 60.66 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.37 रुपये की गिरावट के साथ 4.01 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 4.3 रुपये की गिरावट के साथ 200 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 80 पैसे के सुधार के साथ 26.7 रुपये हुआ। सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 4442.5 रुपये की गिरावट के साथ 9028.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 16342.5 रुपये की गिरावट के साथ 24499.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 24.68 रुपये की गिरावट के साथ 30.5 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.65 रुपये की बढ़त के साथ 12.65 रुपये हुआ।

नर्मदा में राजनीतिक भूचाल, भाजपा-कांग्रेस के 1000 से ज्यादा लोग AAP में शामिल हुए

- विधायक चैतर वसावा और दिल्ली के विधायक अखिलेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भाजपा-कांग्रेस के हजारों लोग AAP में शामिल हुए
- नर्मदा जिले के चीकदा गांव में AAP की भव्य परिवर्तन सभा आयोजित हुई, विधायक चैतर वसावा ने दी उपस्थिति
- हमारी सरकार में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे – चैतर वसावा
- सरकार बनते ही ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे – चैतर वसावा
- वन अधिकार कानून के तहत लंबित अधिकार अवश्य दिए जाएंगे – चैतर वसावा
- जिले के 181 गांवों में स्कूल नहीं हैं, 505 शिक्षकों के पद खाली हैं – चैतर वसावा
- आदिवासी युवा पुलिस, IAS, IPS, डॉक्टर और शिक्षक बनें, इसके लिए AAP लगातार प्रयासरत – चैतर वसावा
- मनरेगा का नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती, घोटालों का जवाब जनता आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनावों में देगी – चैतर वसावा
- 2027 में गुजरात में परिवर्तन लाकर AAP की सरकार बनाएंगे – चैतर वसावा
- आदिवासियों पर अन्याय होगा तो हम सड़क पर उतरेंगे – चैतर वसावा

जीएनएस)। अहमदाबाद/नर्मदा/भरूच/गुजरात। नर्मदा जिले के चीकदा गांव में AAP की भव्य परिवर्तन सभा आयोजित की गई, जिसमें AAP विधायक चैतर वसावा, दिल्ली से आए विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। विधायक चैतर वसावा और दिल्ली के विधायक अखिलेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भाजपा-कांग्रेस के 1000 से भी ज़्यादा लोग AAP में शामिल हुए थे। साथ ही साथ इस सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और AAP को समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों, विकास और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और पार्टी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चैतर वसावा ने कहा कि आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार वर्षों से केवल कागजों पर ही रहे हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही निश्चित रूप से जमीन पर लागू किया जाएगा। सरकार बनते ही आदिवासी समाज की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और वन अधिकार कानून के तहत जिन लोगों के अधिकार लंबित हैं, उन्हें उनके अधिकार दिए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 505 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में भरा जाएगा। इसके अलावा 181 गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां स्कूल शुरू किए जाएंगे और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। जिले में 1200 से अधिक बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, जिसे दूर करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी और बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के प्रयास किए जाएंगे। युवाओं के भविष्य पर बात करते हुए चैतर वसावा ने कहा कि आदिवासी युवा पुलिस, IAS, IPS, डॉक्टर और शिक्षक बनें, इसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार चिंतित और प्रयासरत है। लेकिन भाजपा सरकार की तानाशाही और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण आदिवासी समाज को उचित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास की ग्रांट का उपयोग अपने प्रचार और कार्यक्रमों के लिए करती है। आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में सत्ता प्राप्त किए बिना आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान करना कठिन है। उन्होंने 2027 में पूरे गुजरात में परिवर्तन लाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प व्यक्त किया। सांसद मनसुख वसावा पर निशाना साधते हुए आप नेता चैतर वसावा ने सार्वजनिक चर्चा और डिबेट के लिए तैयारी जताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में कई बार आदिवासी समाज के मुद्दे उठाए हैं, जबकि भाजपा सांसद ने लोकसभा में आदिवासी समाज के लिए क्या किया है, यह जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। विधायक चैतर वसावा ने आगे कहा कि डेडियापाड़ा की जनता की एकता और शक्ति ऐसी है कि आज देश के प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी डेडियापाड़ा आना पड़ता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस सहित अन्य दलों के दिग्गज नेता भी डेडियापाड़ा आएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। इस मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश-विदेश से कोई भी नेता आए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों में जागरूकता फैलाने, लोगों को एकजुट करने और लोगों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा हो, सड़क हो या मैदान—जहां भी जरूरत पड़े, वे जनता की आवाज उठाते हैं, जो भाजपा सरकार को पसंद नहीं है। भाजपा के कुछ नेता और उनके समर्थक लोगों पर दबाव डालने के लिए फोन करते हैं और लोगों को डेडियापाड़ा न आने देने के प्रयास करते हैं। लेकिन यह शक्ति और हिम्मत केवल मेरी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि मेरे साथ सरपंच, जिला प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकर्ता, युवा, बुजुर्ग तथा माता-पिता का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसी जनसमर्थन के कारण मैं इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। मनरेगा सहित विभिन्न मुद्दों पर नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती—ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनावों में देगी। उन्होंने आदिवासी समाज के पारंपरिक वन अधिकारों पर स्पष्ट कहा कि आदिवासी समाज इस जंगल में आदिकाल से निवास करता आया है और लकड़ी, बांस तथा अन्य वन उपज पर उनका अधिकार है। इस मुद्दे पर वन विभाग को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आदिवासियों पर अन्याय हुआ तो वे सड़क पर उतरेंगे।

डांगरवा स्टेशन यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के महेसाणा-जगुदन स्टेशनों के बीच ब्रिज नं. 971 एवं डांगरवा स्टेशन यार्ड में ब्रिज नं 1014 के पुनर्निमाण के संबंध में इंजीनियरिंग कार्य हेतु 05.02.2026 को ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जो निम्नानुसार हैः-

पूर्णतः रद्द ट्रेन

दिनांक 05.02.2026 की ट्रेन संख्या 79435/79436 साबरमती-पाटन-साबरमती डेमू रद्द रहेगी।

आंशिक रद्द ट्रेनेः

दिनांक 05.02.2026 की ट्रेन संख्या 20959/20960 वलसाड-वडनगर-वलसाड एक्सप्रेस गांधीनगर कैपिटल-वडनगर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

दिनांक 04.02.2026 की 19032 योगनगरी ऋषिकेश-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी।

दिनांक 04.02.2026 की 19412 दौलतपुर चौक-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग महेसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया महेसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें। यात्री ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते है।

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन

जीएनएस)। नई दिल्ली। डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली एनसीआर द्वारा राजेंद्र भवन में आयोजित वार्षिक मेल-मिलाप कार्यक्रम में डोगरी–पहाड़ी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और एकता का स्वर ज़ोरदार तरीके से गूंजा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत यह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कर्ण सिंह ने कहा कि डोगरा समाज को कांगड़ा और चंबा जैसे पड़ोसी पहाड़ी-भाषी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक एकता को मज़बूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुभाषिक होना समय की ज़रूरत है, लेकिन मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि नई पीढ़ी को डोगरी बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया गया तो यह भाषा आने वाले समय में संकट में पड़ सकती है। डॉ.सिंह ने भाषा संरक्षण में परिवारों, विशेष रूप से माताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए डोगरों से एकजुट, प्रगतिशील और दूरदर्शी बने रहने की अपील की। उन्होंने इस आयोजन के लिए सुदेश डोगरा और समस्त आयोजक टीम को बधाई भी दी। लोकप्रिय डोगरी-हिमाचली लोकगीत "माये निं मेरिये, जम्मूऐ दी राहे, चंबा कितनी क दूर" में कथित छेड़छाड़ के विरोध में प्रसिद्ध गायक धीरज शर्मा ने गीत को उसके मूल शब्दों में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में ज्योति गुप्ता सहित अन्य कलाकारों ने भी भाग लिया। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर जम्मू के प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों की चुप्पी पर निराशा व्यक्त की, जबकि लोकगीतों की सांस्कृतिक चिंताओं की हिफाजत में आवाज़ उठाने वाले हिमाचली कलाकारों की सराहना की।

वरिष्ठ पत्रकार और भाषा कार्यकर्ता रमन केसर ने कहा कि लोकगीतों के साथ छेड़छाड़ पश्चिमी पहाड़ी और डोगरी को अलग-अलग दिखाने का प्रयास है, जिसका एसोसिएशन रचनात्मक और सशक्त ढंग से विरोध करेगी। इस अवसर पर रोहित महाजन, क्लस्टर हेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को ट्राफियां भेंट कर के सम्मानित किया।

कार्यक्रम के आयोजन में कैलाशपति शर्मा, सुदेश डोगरा, जगदीश शर्मा , कुलवीर सिंह , कर्नल सुनील शर्मा, नेहा शर्मा, सतपाल शर्मा और बोधराज ठाकुर, राज रैना जी का विशेष योगदान रहा।

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन पिछले चार वर्षों से लोहड़ी के अवसर पर लगातार यह आयोजन कर रही है। एसोसिएशन ने स्वयं को राजनीति से दूर रखा हुआ है और समाजी-सांस्कृतिक कार्यों में लगी हुई है।

'अब तक का सबसे बड़ा समझौता' - भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर और भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन : फियो अध्यक्ष

जीएनएस)। नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने 'अब तक का सबसे बड़ा समझौता यानी समझौतों के जनक', भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने का तहे दिल से स्वागत किया है, जिसके तहत अमेरिका ने सभी भारतीय निर्मित उत्पादों पर टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और बढ़ावा देने और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि है। इस घटनाक्रम को भारतीय निर्यातकों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर और गेम-चेंजर बताते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि यह समझौता अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और सभी क्षेत्रों में भारत के निर्यात विकास को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

श्री रल्हन ने कहा, "भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना और भारत में निर्मित उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है और भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए बड़े अवसर खोलता है।"

श्री रल्हन ने इस बात पर जोर दिया कि इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और परिधान, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, चमड़े के उत्पाद, रत्न और आभूषण, और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को टैरिफ युक्तिकरण से काफी फायदा होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, "कम टैरिफ न केवल मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेंगे बल्कि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक गहराई से एकीकृत होने में भी मदद करेंगे। यह समझौता क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करेगा, नए निवेश आकर्षित करेगा, और निर्यात-उन्मुख उद्योगों में रोजगार सृजन का समर्थन करेगा।"

जैसा कि संकेत दिया गया है, पहले के लगभग 50 प्रतिशत के स्तर से 18 प्रतिशत तक - आपसी टैरिफ में कमी, अन्य एशियाई आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर होगा। उम्मीद है कि इससे उन ऑर्डरों में तत्काल और पर्याप्त वृद्धि होगी जिन्हें पहले रोक दिया गया था, विशेष रूप से परिधान, कपड़ा, चमड़ा और जूते जैसे श्रम-आधारित क्षेत्रों में, जहां वैश्विक खरीदार आमतौर पर दिसंबर तक गर्मियों के मौसम की सोर्सिंग को अंतिम रूप दे देते हैं। बेहतर मूल्य समानता, बेहतर टैरिफ निश्चितता, और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं में मजबूत खरीदार विश्वास के साथ, ये क्षेत्र आने वाले महीनों में ऑर्डरों में तेजी से वृद्धि और निर्यात विकास में तेजी के लिए तैयार हैं।

फियो अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम और गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा निर्यातकों के हितों की रक्षा करने और आपसी फायदे वाले नतीजे पर पहुंचने के लिए अमेरिकी समकक्षों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में निभाई गई सक्रिय भूमिका की भी सराहना की।

श्री एस सी रल्हन ने कहा, "यह समझौता वैश्विक बाजारों को मुक्त, निष्पक्ष और नियमों पर आधारित व्यापार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संकेत देता है। फियो को विश्वास है कि यह घटनाक्रम भारत को अपने दीर्घकालिक निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और एक विश्वसनीय वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा।"

फियो प्रमुख ने समझौते से मिलने वाले फायदों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी मुद्दे को समय पर हल करने के लिए निर्यातकों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की फियो की प्रतिबद्धता को दोहराया।

विश्व कैंसर दिवस: GCRI बना देश का भरोसेमंद कैंसर उपचार केंद्र, 26,810+ मरीजों को मिला नया जीवन, 9,140+ बाहरी राज्यों से पहुंचे

- वर्ष 2025 में 2.59+ लाख OPD विज़िट्स, 17,800+ सर्जरीज़ और 50,130+ कीमोथेरेपीज़ GCRI में संपन्न
- मात्र 6 महीनों में GCRI में 50 रोबोटिक सर्जरीज़, पिछले 3 वर्षों में 40 अत्याधुनिक HIPEC प्रोसीजर्स हुए
- 2021–2025 के बीच अत्याधुनिक PET-CT स्कैन भी 1,813 से बढ़कर 6,333 हुई
- अक्टूबर 2021 से संचालित 'नो-कॉस्ट कैंसर स्क्रीनिंग OPD' में अब तक 50,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग, 118 कैंसर केसेस की प्रारंभिक अवस्था में पहचान

जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GCRI), अहमदाबाद ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि वह केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए कैंसर उपचार, अनुसंधान, रोकथाम और प्रारंभिक पहचान का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। GCRI के सुदृढ़ीकरण और विस्तार की जो आधारशिला वर्षों पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के दौरान रखी गई थी, उसी सतत नीति-दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर उपचार का भरोसेमंद केंद्र बनकर उभरा है। विश्व कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर जारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में GCRI में 26,810 से अधिक नए कैंसर मरीजों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 9,147 मरीज गुजरात के बाहर से आए। इनमें सबसे अधिक मरीज मध्य प्रदेश (4,572), राजस्थान (2,678), उत्तर प्रदेश (1,094), महाराष्ट्र (279) और बिहार (288) से पहुँचे। ये आँकड़े बताते हैं कि GCRI अब एक सशक्त 'नेशनल रेफरल सेंटर' के रूप में स्थापित हो चुका है, जहाँ देश के लगभग सभी राज्यों से कैंसर मरीज उपचार के लिए पहुँच रहे हैं।

रोबोटिक सर्जरी और HIPEC के माध्यम से GCRI का सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में क्रांतिकारी कदम

अत्याधुनिक तकनीक से कैंसर उपचार उपलब्ध कराने में गुजरात कैंसर रीसर्च इन्स्टीट्यूट (GCRI) ने नया मानदंड स्थापित कर लिया है। यहाँ अब 50 रोबोटिक असिस्टेड कैंसर सर्जरीज़ और HIPEC (हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी) जैसी अत्याधुनिक उपचार सुविधाएँ भी उपलब्ध हो गई हैं। मात्र 6 महीनों में GCRI में रिकॉर्ड 50 रोबोटिक असिस्टेड कैंसर सर्जरीज़ हुई हैं और वहीं पिछले 3 सालों में कैंसर से संबंधित 40 HIPEC प्रोसीजर्स भी सफलतापूर्वक की गई हैं। उल्लेखनीय है कि HIPEC एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो पेट के भीतर फैले कैंसर में उपयोग होती है, और अब यह चुनिंदा तकनीक मरीजों के लिए GCRI में उपलब्ध है। इसी तरह PET-CT स्कैन (Positron Emission Tomography - Computed Tomography) भी कैंसर की जाँच और इलाज में इस्तेमाल होने वाली सबसे उन्नत और सटीक तकनीकों में से एक है। आसान भाषा में कहें तो, यह दो अलग-अलग तरह की जाँचों (PET और CT) का एक 'हाइब्रिड' या मिश्रण है जो शरीर के अंदर की बहुत बारीक जानकारी देता है। GCRI में PET-CT जाँच की संख्या भी वर्ष 2021 के सापेक्ष 1,813 से बढ़कर 2025 में 6,333 हो गई है।

विश्व कैंसर दिवस पर GCRI करेगा 500 कैंसर सर्वाइवर्स का सम्मान

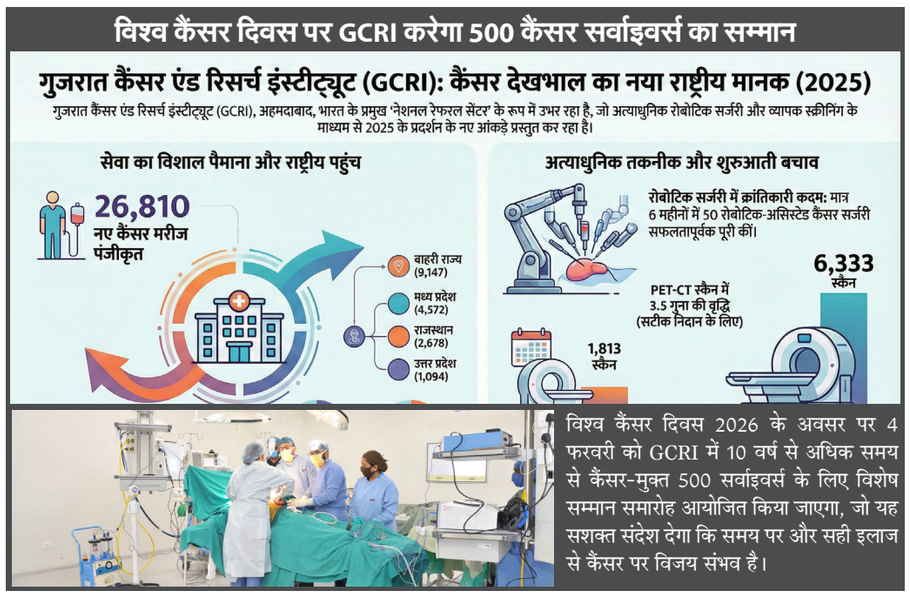

विश्व कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर 4 फरवरी को GCRI में 10 वर्ष से अधिक समय से कैंसर-मुक्त 500 सर्वाइवर्स के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जो यह सशक्त संदेश देगा कि समय पर और सही इलाज से कैंसर पर विजय संभव है।

वर्ष 2025 में GCRI में 2.59+ लाख OPD विज़िट्स, 17,800+ सर्जरीज़ और 50,130+ कीमोथेरेपीज़ संपन्न

कैंसर उपचार में GCRI की बढ़ती विश्वसनीयता से वर्ष 2025 में 2.59+ लाख OPD विज़िट्स दर्ज की गईं। इसी अवधि में 17,800+ सर्जरीज़ जिनमें 50 बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शामिल हैं, हुई हैं। साथ ही, इसी वर्ष कैंसर उपचार के लिए 50,130+ कीमोथेरेपीज़, 5,852 रेडिएशन ट्रीटमेंट्स और 24.6 लाख से अधिक लैब जाँचें भी की गईं। इतना ही नहीं, कैंसर की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए GCRI ने 2025 में पूरे गुजरात में 110 सामुदायिक स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए, जिनमें 12,000 से अधिक लोग शामिल हुए। अक्टूबर 2021 से संचालित 'नो-कॉस्ट कैंसर स्क्रीनिंग OPD' में अब तक 50,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें से 118 कैंसर मामलों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हुई। इसी तरह, HIV संक्रमित महिलाओं (PLHA) के लिए चलाए गए HPV DNA स्क्रीनिंग कार्यक्रम में भी 1,400 से अधिक महिलाओं की जाँच की गई जिनमें 21 प्रतिशत HPV पॉजिटिव पाई गईं और आगे की जाँच में 57 सर्विक्स कार्सिनोमा इन-सिटू (CIN) केस सामने आए, जिससे समय रहते इलाज संभव हो सका।

अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल परिवर्तित मार्ग से चलेगी

जीएनएस)। दक्षिण रेलवे के चेन्नई एग्मोर (MS) स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य हेतु 60 दिनों का ब्लॉक लिया गया है, जिसके कारण अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

ट्रेन संख्या 09419 अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल 05 फरवरी 2026 से 02 अप्रैल 2026 तक परिवर्तित मार्ग वाया रेनिगुंटा-अरक्कोणम नॉर्थ कैबिन-मेलपक्कम-काटपाडी-वेलूर केंट-विल्लुपुरम के रास्ते चलेगी।

इस दौरान यह ट्रेन अरक्कोणम, पेरम्बूर, चेन्नई एग्मोर, ताम्बरम और चेंगलपट्टू स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

ट्रेन संख्या 09420 तिरुचिरापल्ली-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल 08 फरवरी 2026 से 29 मार्च 2026 तक परिवर्तित मार्ग वाया वेलूर केंट-काटपाडी-मेलपक्कम-अरक्कोणम नॉर्थ कैबिन-रेनिगुंटा के रास्ते चलेगी।

इस दौरान यह ट्रेन चेंगलपट्टू-ताम्बरम और चेन्नई एग्मोर, पेरम्बूर, अरक्कोणम स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

मार्ग परिवर्तन के दौरान इस ट्रेन को तिरुत्तणि स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

ट्रेनों के ठहराव, मार्ग और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।